दूरभाषः 23468300

फैक्सः 23702440

Directoriipa9@gmail.com

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,

नई दिल्ली

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2022

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2022 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार राशि निम्नवत् हैः

प्रथम पुरस्कारः 10,000/– रूपये

द्वितीय पुरस्कारः 7,000/–रूपये

तृतीय पुरस्कारः 5,000/– रूपये

जिस प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता में एक बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह प्रतियोगी दुबारा उसी श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के किसी पुरस्कार का हकदार नहीं होगा। निबंधों के संयुक्त लेखन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा संयुक्त रूप से लेखकों द्वारा लिखित किसी भी निबंध पर प्रतियोगिता के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय हैं–

1. महामारी के बाद की अवधि में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन
2. चौथी औद्योगिक क्रांति और शासन
3. नेतृत्व और समाज में महिलाओं की विकसित भूमिका

निबंध लेखकों से अपनी प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित है:

विषय (1) : महामारी के बाद की अवधि में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद् बिंदु शामिल किए जाने चाहिए:

महामारी के बाद की अवधि में, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। कोविड महामारी के कारण परिवर्तन और चुनौतियाँ केवल सामाजिक-आर्थिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि घरेलू प्रकोपों और स्वास्थ्य प्रणालियों में उनके प्रभाव देखे गए हैं। कोविड महामारी के प्रमुख प्रभावों को रोजगार, गरीबी, महिलाओं की स्थिति, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर देखा गया है। महामारी ने आर्थिक कल्याण और सामाजिक पूंजी निर्माण में एक अथाह नुकसान किया है। व्यक्तियों के लिए अस्थिर वातावरण, व्यावसायिक गतिविधियों का नुकसान और रोजगार का नुकसान, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की गति को बाधित और धीमा करने वाले कोविड महामारी की प्रमुख शाखाएँ हैं। कमजोरों की पीड़ा अर्थात् निराश्रितों, महिलाओं, विकलांगों, बच्चों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों आदि ने जीवन और आजीविका को खतरे में डाल दिया है। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला द्वारा ट्रिगर किए गए ब्लॉकचेन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन मुद्दों को हल करने के लिए इक्विटी आधारित लचीलापन हमारी सरकार द्वारा किया गया एक अनूठा कदम रहा है। समाज और अर्थव्यवस्था को "हमेशा की तरह व्यवसाय" में वापस लाने के लिए संचार और सहयोग के नए रूपों, कल्पनाशील डिजाइन सोच, प्रबंधन की नई शैलियों के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक नीतियों में भागीदारी के नए उपकरण और रूप सामने आए हैं। इसने जीवन और आजीविका के लिए एक 'नए सामान्य' को जन्म दिया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि-खाद्य क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन प्रणाली, यात्रा, व्यापार, रसद और माल वितरण, श्रम बाजार का परिवर्तन और कार्यबल अधिकारों में 'नए सामान्य' से निपटने के लिए एक भूकंपीय परिवर्तन आया है। सामाजिक व्यवस्था और

प्रथाओं को आकार देने और पुनर्व्यवस्थित करने में सामाजिक संस्थाओं की घटती भूमिका को नए सामान्य में नई परिभाषा मिली है। वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल कम्युनिटी का अस्तित्व,' वर्क-फ्रॉम-होम' संस्कृति, संक्रामक रोगों पर अतिरिक्त सतर्क रहना, 'आत्मनिर्भर' (आत्मनिर्भर) पर अधिक ध्यान देना, श्रम विभाजन की तीव्रता में कमी, और अस्तित्व के लिए प्रमुख अभिविन्यास है। महामारी के बाद की अवधि में उचित आधार प्राप्त किया। तुलना में, गैर-निष्पादित आस्तियों के उच्च स्तर, विशेष रूप से एसएमई और अपर्याप्त रूप से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणालियों पर 'बिल्ड-बैक-बेहतर' पर ध्यान दिया जाता है। तैयारियों, रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का महत्व सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक जीवन को फिर से जीवंत और पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक रूप से फैले और स्वीकृत मंत्र हैं। लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, आजीविका, कमजोर वर्गों और विभिन्न मानवीय मुद्दों के संबंध में प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। महामारी के बाद की अवधि ने अंततः एक ऐसे विघटन की शुरुआत की है जहाँ व्यक्तियों के कुल प्रयासों के योग के माध्यम से सामाजिक शक्ति को उत्प्रेरित किया जा सकता है।

इस प्रकार, निबंध के फोकस क्षेत्र में निम्न शामिल हो सकते हैं:

1. महामारी के बाद की अवधि में कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित मुद्दे,
2. महामारी के बाद की अवधि में विनिर्माण क्षेत्र, आगे और पीछे दोनों लिंकेज,
3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) और एक अपर्याप्त पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली, और महामारी के बाद की अवधि में निजी सहयोग क्षेत्र,
4. महामारी के बाद की अवधि में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता,
5. महामारी के बाद की अवधि में प्रमुख विकलांगता, स्वास्थ्य देखभाल और लिंग अंतर संबंधी चिंताएं,
6. महामारी के बाद की अवधि में जनजातीय जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के नए आयाम,

7. महामारी के बाद की अवधि में कौशल के माध्यम से रिवर्स प्रवासियों की रोजगार क्षमता में सुधार, और
8. परिवारों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को अपूरणीय क्षति और महामारी के बाद की अवधि का सामना करना पड़ा।

विषय (2) : चौथी औद्योगिक क्रांति और शासन

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद् बिंदु शामिल किए जाने चाहिएः

यह प्रतिमान बदलाव - चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) - भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों के संलयन की विशेषता है (चित्र 1 देखें)। इस क्रांति को लागू करने वाली लोकप्रिय तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), डेटा एनालिटिक्स, 3-डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हैं। चालक रहित स्वचालित वाहन, सर्जरी करने वाले रोबोटिक हथियार, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उद्योग 4.0 के परिणामों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अपने नाम के बावजूद, उद्योग 4.0 की अवधारणा केवल विनिर्माण उद्योग के बारे में नहीं है बल्कि इसने विनिर्माण और सेवाओं के बीच की खाई को कम किया है। उद्योग 4.0 के व्यापक अर्थ में स्मार्ट परिवहन और रसद, स्मार्ट भवन, तेल और गैस, स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट गांवों और शहरों जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। इसलिए, यह मैक्रो, मेसो, छोटे और सूक्ष्म स्तरों पर प्रभाव के साथ वैश्विक औद्योगिक बाजारों में और उनके डिजिटल परिवर्तन से संबंधित है। उद्योग 4.0 सतत विकास लक्ष्य-9 के सभी पहलुओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है अर्थात लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। इसके अलावा, आपूर्ति और मांग दोनों ही तरफ से अधिकांश अन्य एसडीजी के लिए इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

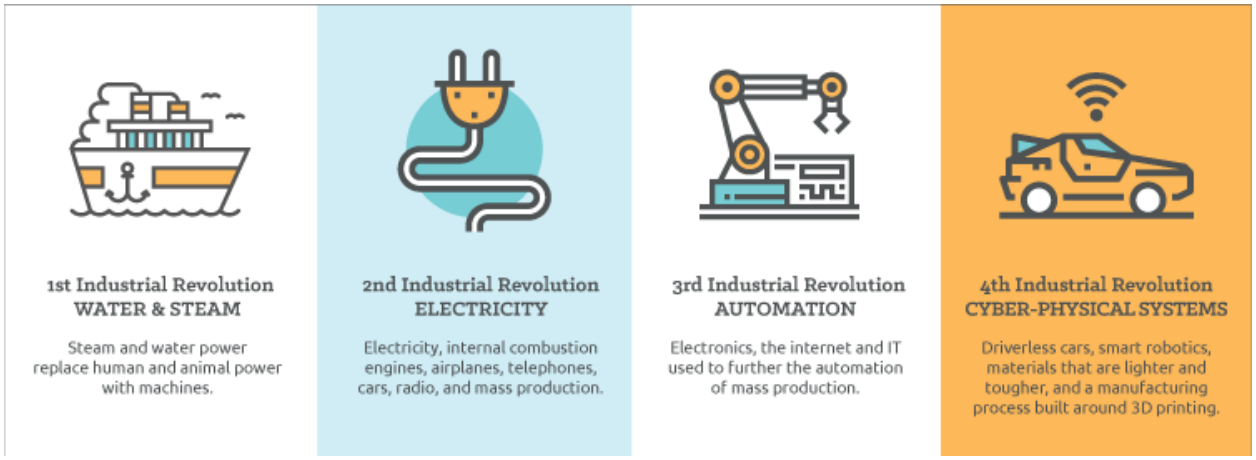

चित्र 1 औद्योगिक क्रांति - एक प्रतिमान बदलाव

उद्योग 4.0 छह डिजाइन सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात् इंटरऑपरेबिलिटी; वर्चुअलाइजेशन; विकेंद्रीकरण, वास्तविक समय की क्षमता; सेवा अभिविन्यास; और प्रतिरूपकता (चित्र 2 देखें)।

किसी भी अन्य व्यवधान की तरह, उद्योग 4.0 में मानव जीवन को बदलने की क्षमता है और यह मानव जाति के लिए असंख्य अवसरों और चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। यह परिवहन और संचार की लागत में पर्याप्त कमी, जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार और दक्षता आसमान छूने का वादा करता है। लेकिन असमानता की खाई को चौड़ा करने, श्रम बलों के विघटन और नागरिक और राज्य के बीच तेजी से कमजोर होने जैसे खतरे हैं।

चित्र 2 उद्योग 4.0 डिजाइन सिद्धांत

प्रौद्योगिकी और डेटा क्रांति का आक्रमण अनिवार्य रूप से शासन और लोकतंत्र के चेहरे को उसके वर्तमान स्वरूप से बदल देगा। प्रौद्योगिकी और सूचना समाज में सबसे निचले वर्ग को सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीयकरण करेगी, जिससे आम आदमी को उन तरीकों से सशक्त बनाया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखे गए। एक ओर, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह बेहतर दक्षता, चपलता, नवाचार, ग्राहक अनुभव और बेहतर स्थिरता के लिए प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सुविधाकर्ताओं की भूमिका निभाएगी और उद्योग को नियंत्रित करेगी। लेकिन दूसरी ओर, सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उद्योग 4.0 के लाभ भारतीय उद्योग जगत तक पहुंचें, जिसमें लगभग 60 मिलियन उद्यम शामिल हैं और देश के कुल विनिर्माण उत्पादन यानी एमएसएमई खंड में 45 प्रतिशत का योगदान देता है। उद्योग 4.0 के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को रोजगार को प्रोत्साहित करने और कौशल अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

लेखकों ने उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की आलोचनात्मक जांच करने और जनता तक पहुंचने के लाभों को सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने की अपेक्षा की।

विषय (3) : नेतृत्व और समाज में महिलाओं की विकसित भूमिका

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद् बिंदु शामिल किए जाने चाहिए:

एक समतावादी समाज का निर्माण: सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाए, भारत सरकार का आदर्श वाक्य, एक बहुत ही समावेशी नारा है जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण और आनंद के लिए एक समाज का विकास करना है। भविष्य में इस पाठ्यक्रम का अनुसरण करने से निस्संदेह एक समतावादी समाज का निर्माण होगा।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अनुसार, शीर्ष व्यावसायिक नेतृत्व स्तरों पर महिलाएं वैश्विक स्तर पर केवल 24% वरिष्ठ पदों पर हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ और भी कम हैं। भारत के वरिष्ठ अधिकारियों में नेतृत्व के पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है, जो विशेष रूप से चिंताजनक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 136वें स्थान पर है।

सभी आधुनिक औद्योगिक देशों में बोर्डरूम और सरकारों में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, एस एंड पी 500 निगमों (थॉमस, 2018) में सीईओ पदों के 6% से कम और वैश्विक राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व पदों के 5% से कम के लिए लेखांकन। जबकि लिंग अंतर कम हो गया है, व्यापार और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति में बाधाएं महत्वपूर्ण हैं।

संसद में महिलाओं की संख्या के मामले में भारत सबसे निचले पायदान पर है। जून 2019 में लोकसभा में 14.39% महिला सांसदों की चोटी के बावजूद, भारत अभी भी संसद में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में 140 देशों

से भी बदतर है। महिला विधायकों के अनुपात का वैश्विक औसत 24.6% था। बाधाओं के बावजूद, महिलाएं कई देशों में नेतृत्व के पदों पर आगे बढ़ रही हैं, यहां तक कि संगठनों और सरकारों के उच्चतम स्तरों पर भी। मीडिया अक्सर शेरिल सैंडबर्ग जैसे व्यावसायिक अधिकारियों, सना मारिन जैसे प्रधानमंत्रियों और क्रिस्टीन लेगार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुखों को कवर करता है। उनकी उपस्थिति कांच की छत के रूपक को आराम देती है: महिलाओं को ऐसे पदों को प्राप्त करने से कोई पूर्ण बाधा नहीं है। नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं की उन्नति कर्षण प्राप्त कर रही है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं सक्षम नेताओं के रूप में काम करती हैं, यह अब असामान्य नहीं लगेगा कि एक महिला नियंत्रण में है। वास्तव में, महिला नेता आधुनिकतावाद और आगे की सोच वाले नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए समकालीन सक्रियता के साथ अपने लिंक के कारण आई हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कैरियर विकास, विविधता और कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने वाले सेटअप के माध्यम से महिलाओं को वैश्विक नेतृत्व दक्षताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रणाली को मजबूत करके नेतृत्व की भूमिकाओं में उन्नत किया जा सकता है।

एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में, हमारे कानूनों, विकास रणनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों ने कई क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से महिलाओं के मामलों के प्रति दृष्टिकोण कल्याण से विकास की ओर स्थानांतरित हो गया है। हाल के वर्षों में, महिला सशक्तिकरण को महिलाओं की स्थिति स्थापित करने में प्राथमिक मुद्दा माना गया है।

निबंध लेखक नीचे उल्लिखित किसी एक या अधिक क्षेत्रों पर जोर दे सकते हैं।

1. नेताओं और महिलाओं के बारे में रूढ़ियाँ
2. नेताओं के रूप में महिलाओं का भविष्य
3. समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को बदलना
4. बीटिंग द ऑड्स: वीमेन इन एल ईडरशिप

5. नेतृत्व और समाज में महिलाओं को शामिल करने के लिए सरकारों की विभिन्न नीतियां
6. लिंग और लिंग: बदलती गतिशीलता
7. एक समतामूलक समाज का निर्माण

निबंध के सामान्य दिशानिर्देश

निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। निबंध लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए। प्रतियोगी को निबंध में प्रयुक्त शब्दों की कुल संख्या बतानी होगी अन्यथा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5500 से अधिक शब्दों वाला निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निबंध पृष्ठ के केवल एक ही तरफ दोहरे स्थान के साथ साफ–साफ टाईप किया हुआ होना चाहिए। जिन प्रविष्टियों में इस निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं किया जायेगा उन्हें अस्वीकृत किया जा सकता है। कल्पित नाम के साथ निबंध की तीन प्रतियां जमा की जानी चाहिए। प्रतियोगी का पूरा असली नाम तथा पता एक अलग कागज़ पर दिया जाना चाहिए और यह कागज एक सीलबंद लिफाफे में रखा होना चाहिए जिस पर ऊपर कल्पित नाम के साथ ही निम्न शब्द अंकित होने चाहिए।

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2022, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सभी निबंध पंजीकृत डाक द्वारा निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110002 को भेजे जाने चाहिए। ये निबंध 15 सितम्बर, 2022 तक

अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2022" लिखा होना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्णायक गण इन निबंधों पर अपना निर्णय देंगे और इनके द्वारा दिया गया पुरस्कार अंतिम होगा। यदि प्राप्त निबंधों में से कोई भी आवश्यक मानक स्तर तक नहीं पहुंचता है तो संस्थान को यह अधिकार है कि वह किसी को भी पुरस्कार न दे। पुरस्कृत निबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा लेखक की संयुक्त बौद्धिक संपत्ति होंगे।

कृपया ध्यान दें: अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110002 को लिख सकते हैं।